22

जनसंख्या संघटन

पिछले पाठ में हमने भारत में जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व के कारणों एवं परिणामों पर भी ध्यान दिया था। हमने पिछले सौ वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों एवं परिणामों पर भी विचार किया था। इस पाठ में हम कुछ नए आयामों के साथ भारतीय जनसंख्या के संघटन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उन अधिवासों की अवस्थिति और आकार को अंकित करना चाहेंगे, जहां लोग रहना पसंद करते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं? इसमें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का संघटन शामिल है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है और अधिक महत्वपूर्ण है उनका समाज में दर्जा क्या है। हमारी जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु होगा भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना और उसके प्रभाव। तब हम विशुद्ध जनसांख्यिकी से हट कर जनसंख्या संरचना के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम की ओर जाएंगे। इससे हमें अपने समाज की भलायी और धार्मिक संरचना के बारे में पता चलेगा। अंत में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनंसख्या, अवस्थिति और वितरण पर नजर डालेंगे। अंत में लेकिन सबसे आवश्यक होगा कि अपने देश में साक्षरता के स्तर का भी अध्ययन करें। यह सारे विश्लेषणात्मक तत्व हमें जनसंख्या को मात्र संख्या ही नहीं अपितु मानवीय संसाधन के रूप में समझने में सहायता करेंगे।

सीखने के प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी:

- भारतीय जनसंख्या की ग्रामीण-शहरी एवं आयु संरचना तथा लिंगानुपात की व्याख्या करता है;
- साक्षरता के स्तरों में स्थानिक और अस्थायी परिवर्तन का वर्णन करता है;
- जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक और भाषायी संरचना का विश्लेषण करता है और
- लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जनसांख्यिकी मुद्दों का वर्णन करता है।

टिप्पणी

22.1 ग्रामीण-शहरी संघटन

बस्तियों के आकार और आबादी के आधार पर जनसंख्या को दो भागों, शहरी और ग्रामीण, में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई छोटे आकार की बस्तियों की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। शहरी जनसंख्या उसे कहते हैं जो शहरों और कस्बों में बड़े आकार की बस्तियों में रहते हैं। यद्यपि यह विभाजन मुख्यत: व्यावसायिक संरचना पर आधारित है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र उसको कहा जाता है जहां जनसंख्या का तीन चौथाई या उससे अधिक प्राथमिक व्यवसायों जैसे खेती, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और उत्खनन का काम करते हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां जनसंख्या के तीन चौथाई से अधिक गैर कृषि कार्यों जैसे विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, संचार, बैकिंग तथा सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन इत्यादि।

तालिका 22.1 भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

जनगणना वर्ष	**कुल जनसंख्या ग्रामीण**	**प्रतिशत शहरी**
1901	89.2	10.8
1901	89.2	10.8
1911	89.7	10.3
1921	88.8	11.2
1931	88.0	12.0
1941	86.1	13.9
1951	82.7	17.3
1961	82.0	18.0
1971	80.1	19.9
1981	76.7	23.3
1991	74.3	25.7
2001	72.2	27.8
2011	68.8	31.2

स्रोत: भारत की जनगणना

टिप्पणी

भारत की कुल जनसंख्या 6,40,867 गांवों और 7935 शहरों में व्याप्त है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। आज भी भारतीय जनसंख्या का 69 प्रतिशत गांवों में रहता है। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात प्रत्येक जनगणना में घटता जा रहा है (तालिका 22.1)। परिणामस्वरूप शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात धीरे-धीरे परंतु लगातार बढ़ रहा है। 1901 में यह 10.8 प्रतिशत जितना कम था और 2011 में यह बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो गया। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? इसका कारण है कि शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। 2010-11 में शहरी जनसंख्या में वृद्धि काफी अधिक 31.8 प्रतिशत थी परंतु ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 12.18 प्रतिशत थी। भारत में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 1991 के बाद से निरंतर घट रही है। हालांकि यह वृद्धि केवल जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के कारण नहीं है। वस्तुतः शहरी जनसंख्या में वृद्धि का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों का प्रवास है। बहुत बार म्युनिसिपल अथवा नगर निगम निकट के गांवों और अर्द्धशहरी क्षेत्रों को अपने में मिलाने के लिए अपनी सीमाओं को बढ़ा लेते हैं।

भारत की शहरी जनसंख्या का आधा केवल पांच राज्यों में है। यह पांच राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश। गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान और केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में देश की शहरी जनसंख्या का 32 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या का शेष बाकी के राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है।

2011 की जनगणना के अनुसार 53 शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इन्हें मेट्रोपालिटन अथवा मिलेनियम प्लस शहर कहते हैं। अकेले इन 53 शहरों में ही कुल जनसंख्या का 37.8 प्रतिशत रहता है। पोलिटन शहरों की तीव्र वृद्धि से कई समस्याएं जैसे आवास, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन की दुकानों के मामले में समस्या आएगी। आइये अब हम भारत में इन शहरों के वितरण के बारे में जानते हैं।

सभी 53 मेट्रोपालिटन शहरों को जनसंख्या के घटते क्रम से व्यवस्थित किया गया है। ये इस प्रकार हैं- मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, गाजियाबाद, इंदौर, पटना, कोजीकोड, भोपाल, त्रिसुर, बडोदरा, आगरा, विशाखापटनम, मल्लापुरम, तिरुवनंतपुरम, लुधियाना, कन्नूर, नासिक, विजयवाड़ा, मदुरई, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद, राजकोट, जमशेदपुर, श्रीनगर, जबलपुर, आसनसोल, वसई-विरार, धनबाद, इलाहाबाद, औरंगाबाद, अमृतसर, जोधपुर, रांची, रायपुर, कोलम, ग्वालियर, दुर्ग-भिलाईनगर, चंडीगढ़, त्रिचिरापल्ली और कोटा।

चित्र 22.1 भारतः मुख्य मेट्रो शहर

पाठगत प्रश्न 22.1

1. नीचे दिए शहरों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

   (द्वितीयक और तृतीयक, बढ़, 53, कम, प्राथमिक)

टिप्पणी

a) ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर से .... है।

b) ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से........................ गतिविधियों में संलग्न है जबकि शहरी जनसंख्या......................... में संलग्न है।

c) शहरी जनसंख्या का अनुपात 1921 से निरंतर....................... रहा है।

d) कुल मिलाकर......................... मेट्रोपालिटन शहर है।

22.2 लिंगानुपात

लिंगानुपात का अर्थ किसी क्षेत्र के प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या मात्र 943 थी। अतः भारत में लिंगानुपात अनुकूल नहीं है। इसका अर्थ है पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम होना। जब पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक होती है तो इसे अनुकूल कहा जाता है। यदि हम पिछले 100 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह देखा गया है कि देश में लिंगानुपात निरंतर घटता रहा है सिवाय वर्ष 1951, 1981, 2001 और अब 2011 में।

तालिका 22.2 भारत में लिंगानुपात 1911 से 2011 तक

जनगणना वर्ष	लिंगानुपात
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1997	927
2001	933
2011	943

जहां तक राज्यों का संबंध है तो केवल केरल में लिंग अनुपात 1058 अनुकूल है। यह देश में सबसे उच्च लिंगानुपात है। राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 877 में है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में पुद्दुचेरी का लिंगानुपात (1001) सबसे अधिक है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात दमन और दियू में है जहां प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की संख्या 618 है। लिंगानुपात के मामले में देश में लगातार कमी देखी जा रही है सिवाय 1951, 1981, 2001 और अब 2011 में नाम मात्र की वृद्धि के।

टिप्पणी

भारत में लिंगानुपात क्यों घट रहा है? भारत में लिंगानुपात घटने के मुख्य कारणों में मातृ मृत्यु दर का अधिक होना तथा लड़कियों की उच्च शिशु मृत्यु दर है। इन दो कारणों का संबंध हमारे समाज में स्त्रियों का दर्जा निम्न होना माना जाता है। हमारे इस सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य के अतिरिक्त समाज में पुरुषों को वरीयता देना भी लिंगानुपात के घटने के कारण है। महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाकर तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देकर महिला मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं ने शिशु मृत्यु दर तथा शिशु जन्म के समय मातृ मृत्यु को रोकने में सहायता प्रदान की है।

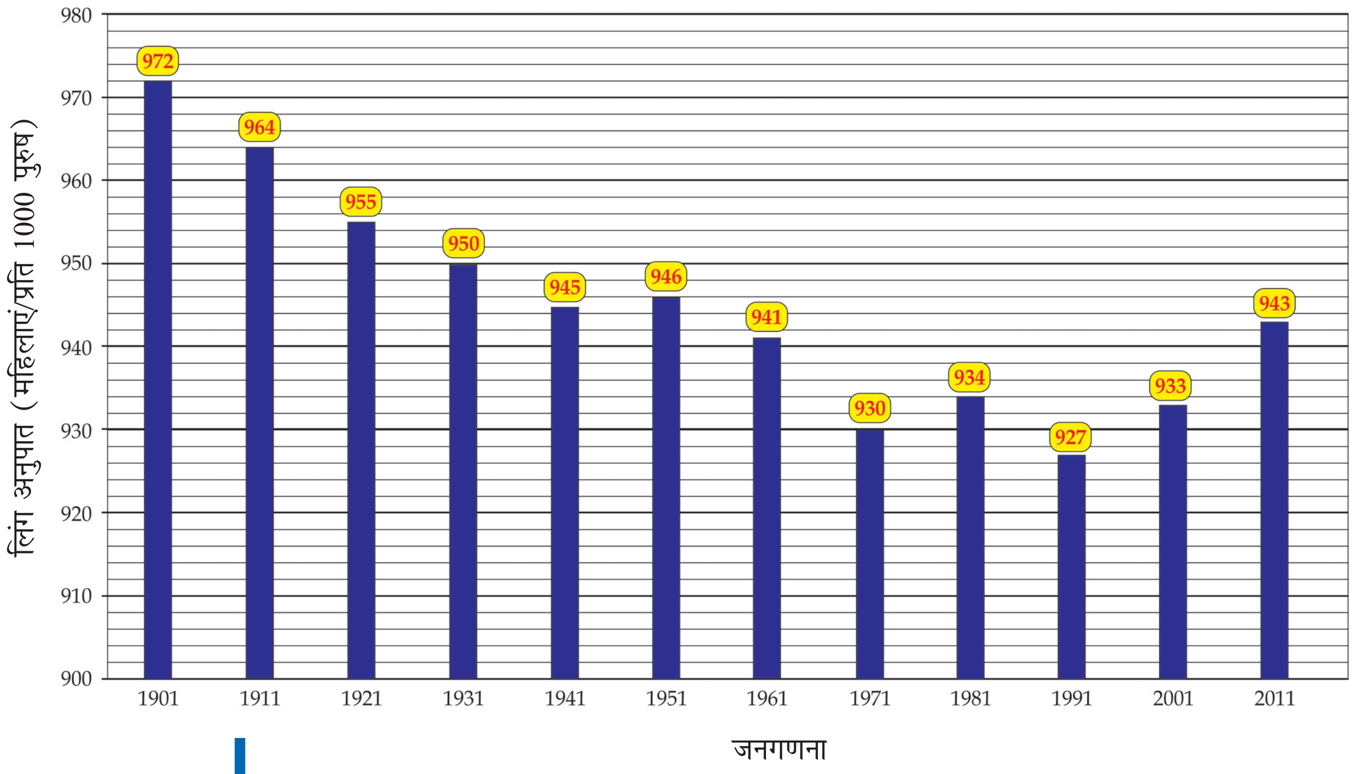

चित्र 22.2 भारत में 1901 से 2011 तक लिंग अनुपात की प्रवृत्ति

लैंगिक न्याय, समानता और महिला सशक्तीकरण

लैंगिक न्याय और समानता एक मानवाधिकार है। महिलाएं इच्छाओं के भार और भय से मुक्त सम्मान के साथ रहने की अधिकारी हैं। गरीबी कम करने तथा विकास को बढ़ाने के लिए लैंगिक समानता एक पूर्व निर्धारित शर्त है। सशक्त महिलाएं पूरे परिवार और समुदायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान देती हैं और वे अगली पीढ़ी की सम्भावनाओं को बेहतर बनाती है। अभी भी महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रत्यक्ष साक्ष्यों के बावजूद महिला सशक्तीकरण मानवाधिकार, गरीबी घटाने, विकास को बढ़ावा देने और दुनिया की आवश्यक चुनौतियों और लैंगिक समानता का वायदा केवल वायदा ही रहा है।

टिप्पणी

प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार

प्रजनन स्वास्थ्य, सभी मामलों में पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को कहते हैं जो प्रजनन प्रक्रिया और इसके सभी वर्गों से सम्बद्ध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों के पास प्रजनन की क्षमता और यह निर्णय करने की स्वतंत्रता हो कि कब, कैसे और कितनी बार प्रजनन की ओर जाना है। इसमें यह शामिल है कि पुरुष और स्त्रियों को अपनी पसंद के सुरक्षित प्रभावशाली और सामर्थ्य अनुसार परिवार नियोजन के स्वीकार्य तरीकों तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, इसके साथ ही प्रजनन को नियमित करने के लिए अपनी पसंद के अन्य तरीके जो कानून के विरुद्ध न हो को चुनने का अधिकार हो। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं तक की पहुंच का अधिकार हो जो स्त्रियों को सुरक्षित गर्भधारण और शिशु जन्म के योग्य बनाएं।

प्रजनन के अधिकारों में कुछ निश्चित मानवाधिकार शामिल हैं जिन्हें पहले ही राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्रों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रासंगिक सहमति पत्रों में शामिल किया जा चुका है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के इस मूलाधिकार की मान्यता पर निर्भर करता है कि वे स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से निर्णय कर सकें कि उन्हें किस समय, कितनी देर बाद और कितनी बार बच्चे चाहिएं तथा उन्हें ऐसा कर पाने के लिए जानकारी और साधन उपलब्ध होने चाहिए साथ ही उन्हें लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य की उच्च मानक सेवाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। इन अधिकारों में सभी को भेदभाव, दबाव और हिंसा से मुक्त प्रजनन संबंधी अधिकार मिलने चाहिए।

प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वे महिलाओं और किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और महिलाओं को नेतृत्व, नियोजन, निर्णय प्रक्रिया, प्रबंधन, क्रियान्वयन, संगठन और सेवाओं के मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए। किशोरों और वयस्कों की प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच बनाने के लिए सूचना, काउंसलिंग और सेवाओं के नवाचार कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को पुरुषों को शिक्षित एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रमों, घरेलू और बच्चे को पालने की जिम्मेदारियों तथा एस.टी.डी. रोगों की रोकथाम में प्रमुख जिम्मेदारी में समान रूप से भागीदारी करनी चाहिए।

पाठगत प्रश्न 22.2

निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए:

a) भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का नाम लिखिए।

b) भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का नाम लिखिए

c) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है?

d) लिंग-अनुपात को परिभाषित कीजिए।

22.3 आयु संरचना

आयु-लिंग पिरामिड लोगों की आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या की संरचना है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर तथा जनसंख्या क्रियाशील और गैर क्रियाशील जनसंख्या की प्रकृति के बारे में संकेत देता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 30.8 प्रतिशत 14 वर्ष तक की आयु तक की जनसंख्या है। 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों का प्रतिशत 60.7 प्रतिशत है तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में जनसंख्या का 8.4 प्रतिशत है। पिछले दशकों में आयु संरचना में कुछ धीमे परिवर्तन हो रहे हैं। एक प्रवृति तो यह है कि 0 से 14 तक के आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है। परंतु 15-59 तक तथा वृद्धजनों की जनसंख्या बढ़ रही है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार 15-59 आयु वर्ग का प्रतिशत 2001 में 56.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 60.7 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही वृद्ध आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या 2001 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 8.7 प्रतिशत हो गई है। 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 35.3 प्रतिशत से घटकर 2011 में 30.8 प्रतिशत हो गया है।

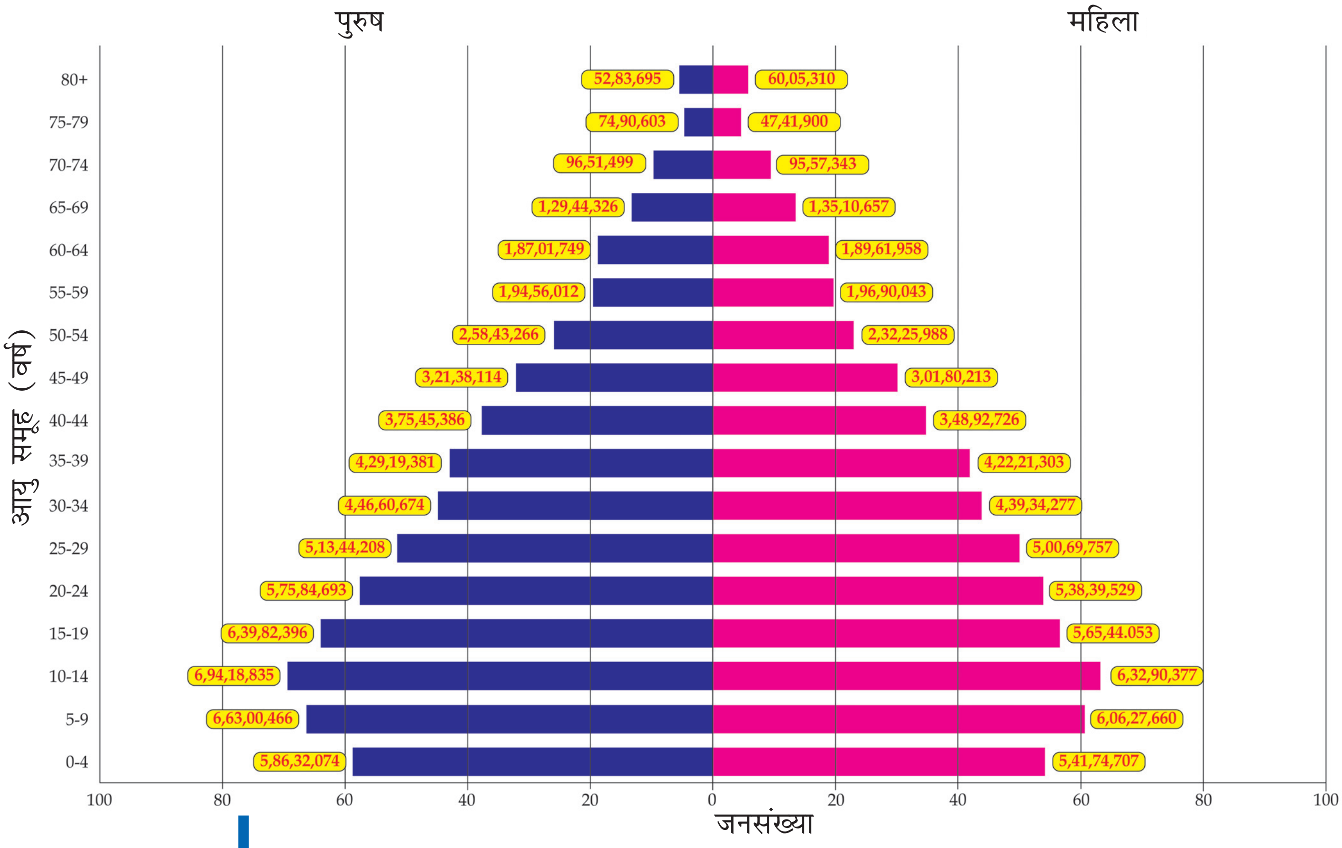

चित्र 22.3 भारत आयु-लिंग संरचना 2011

जनसांख्यिकी विभाजन

क्या आपने कभी यह शब्द सुने हैं? लेकिन आजकल योजना निर्माता, राजनीतिक नेता और शिक्षाविद् इस विषय पर कई दिनों से बात कर रहे हैं। पिछले खण्ड में चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में बहुत बड़ी संख्या जोड़ रहा है। यदि आप इसकी आयु संरचना को देखें तो आपको

ज्ञात होगा कि उसमें बड़ी संख्या 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 17 आयु वर्ग की जनसंख्या 62.5 प्रतिशत थी। आप जानते हैं कि यह आयु वर्ग सबसे सक्रिय लोगों का है। इस सक्रिय कामकाजी जनसंख्या में बढ़ोतरी जनसांख्यिकीय विभाजन का लाभ उठाने में सहायक होती है। साधारण शब्दों में 'जनसांख्यिकीय विभाजन' को सीमित समय के लिए तीव्र आर्थिक विकास के 'अवसरों की खिड़की' के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हालांकि देश के सामने यह चुनौती है कि उन्हें कुशल मानव संसाधन बनाया जाए ताकि सामान्य रूप से वे देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और विशेष रूप से अपना जीवन स्तर सुधार सकें।

22.4 भाषायी संरचना

भारत में भौतिक पर्यावरण की भांति भाषायी विविधता भी है। बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां सैकड़ों की संख्या में हैं। 1961 की जनगणना में भारत में 1652 भाषाओं को मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इनमें से केवल 23 कुल जनसंख्या के 97 प्रतिशत की भाषाएं हैं। संख्या की दृष्टि से बड़ी इन 23 भाषाओं में से भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 22 को भारतीय संविधान की आठवीं सूची में मान्यता देता है। इन भाषाओं में असमी, बंगाली, हिन्दी, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल हैं। उपरोक्त 22 भाषाओं में हिन्दी सबसे अधिक बोली जाती है जबकि संस्कृत सबसे कम बोली जाती है।

पहले इन भाषाओं में से 14 को संविधान में शामिल किया था। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद तीन अन्य भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। बाद में 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया।

ये भाषाएं अलग शब्दों के अर्थ और उच्चारण में भी अलग हैं। किसी भाषा विशेष को बोलने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग उच्चारण और अलग शब्दावली के साथ बोलते हैं। किसी भाषा को बोलने के तरीके में ऐसे बदलाव ने भाषा की बोलियों को जन्म दिया। अत: कोई बोली किसी भाषा के एक भाग के सदृश्य है और उन्हें क्षेत्रीय भाषा भी माना जा सकता है। हिन्दी की कुछ बोलियों के उदाहरण है- राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी और पूर्वी इत्यादि। भाषा, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है और उनकी बोलियां देश के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। इससे देश की संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण बनती है। देश में भाषाओं की सम्पूर्ण क्षेत्रीय पहचान है। मुख्य भाषाओं के वितरण को स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना गया।

संख्या के आधार पर भारत को 12 प्रमुख भाषायी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। भाषायी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश लोग एक सांझी भाषा बोलते हैं। भारत में भाषायी क्षेत्रों की रचना करने वाली भाषाओं में कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी/उर्दू, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम है।

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण और वितरण

यद्यपि भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं एक-दूसरे से अलग हैं तो भी उनको उनके मूल और उत्पत्ति के आधार पर चार भाषायी परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चार भाषायी परिवारों के नाम हैं- आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी-तिब्बती, इंडो-आर्यन।

1. आस्ट्रिक भाषायी परिवार की बोलियां मेघालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मध्य भारतीय जनजातीय पट्टी, विशेषतः संथाल परगना, रांची और मयूरभंज में बोली जाती हैं।

2. चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की भाषा और बोलियां देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जनजातीय लोगों और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम के उप-हिमालयी क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये भाषाएं केन्द्र शासित क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल के कुछ भागों तथा सिक्किम में बोली जाती हैं।

3. द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले अधिकतर भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये भाषाएं तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल तथा केन्द्रशासित क्षेत्र पुद्दुचेरी में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में रहने वाले अधिसंख्य जनजातीय लोग इस परिवार की भाषा बोलते हैं।

4. इडो-आर्यन परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोग देश के उत्तरी और केन्द्रीय भाग में रहते हैं। पूरा उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र इस परिवार की भाषाएं बोलने वालों से भरा पड़ा है। इन भाषाओं को बोलने वालों की बड़ी संख्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बसती है। विभिन्न भाषायी परिवारों की बोलियां बोलने वालों की संख्या में काफी अंतर है। इंडो-आर्यन परिवार की बोली बोलने वाले 70 प्रतिशत लोग हैं तो चीनी-तिब्बती बोलने मात्र .85 प्रतिशत है और द्रविड़ भाषायी परिवार की भाषा बोलने वाले कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत है।

पाठगत प्रश्न 22.3

नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें।

a) आस्ट्रिक भाषायी परिवार से संबंध रखने वाली भाषाओं में से एक भाषा.................. है। (संथाली, हिन्दी, बंगाली)

b) हिन्दी.................... भाषा परिवार से संबंध रखती है। (द्रविड़, इंडो-आर्यन, आस्ट्रिक)

c) आस्ट्रिक भाषाओं के बोलने वाले लोग मूल रूप से...................... क्षेत्रों में संकेन्द्रित हैं। (मध्य भारत का कबीलाई क्षेत्र, पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र)

22.5 धार्मिक संरचना

भारतीय समाज में बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक समुदाय हैं। लेकिन मोटे तौर पर सात प्रमुख धर्म हैं।

अधिकांश लोग इन धर्मों में से किसी एक के अनुयायी हैं। ये हैं हिन्दू, इस्लाम, इसाई, जैन, बौद्ध, सिक्ख और पारसी। भारत में हिन्दू सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है।

तालिका 22.4 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर जनसंख्या

क्रमांक	**धर्म**	**संख्या करोड़ों में**	**प्रतिशत**
1.	हिन्दू	96.63	(79.8 प्रतिशत)
2.	इस्लाम	17.22	(14.2 प्रतिशत)
3.	इसाई	2.78	(2.3 प्रतिशत)
4.	सिक्ख	2.08	(1.7 प्रतिशत)
5.	बौद्ध	.84	(0.7 प्रतिशत)
6.	जैन	.45	(0.4 प्रतिशत)
7.	अन्य धर्म और सम्प्रदाय	.79	(.7 प्रतिशत)
8.	अंकित नहीं	0.25	(0.2 प्रतिशत)

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 79.8 प्रतिशत हिन्दू धर्म का अनुयायी है। इस धर्म के अनुयायी भारत के उत्तरी मैदानों तथा पठारी क्षेत्र के उत्तरी भाग में अधिक सकेन्द्रित है। हालांकि वे भारत के अन्य भागों में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं सिवाय कुछ पूर्वोत्तर राज्यों एवं केन्द्रशासित लक्षद्वीप के। लेकिन अन्य धार्मिक समुदायों का वितरण निरंतर नहीं है और केवल कुछ ही जगहों पर उनका सकेन्द्रण अधिक है।

मुसलमानों की अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है जिसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा भाग जम्मू-कश्मीर और केन्द्रशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में रहता है। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त असम और केरल ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों की काफी आबादी है। यदि हम स्थानिक वितरण को देखें तो ज्ञात होगा कि सिवाय केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इनमें से अधिकांश राज्य उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में है।

इसाइयों की सबसे बड़ी आबादी केरल राज्य में पाई जाती है जिसके बाद तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश का स्थान आता है। यदि हम कुल संख्या के भाग के रूप में देखें तो ज्ञात होता है कि कुछ उत्तरपूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में बहुत बड़ा भाग रहता है। जहां सिक्खों की बात है तो कुल सिक्ख जनसंख्या का एक चौथाई भाग केवल पंजाब में रहता है। पंजाब के अतिरिक्त निकट के राज्यों हरियाणा और राजस्थान में भी सिक्ख जनसंख्या का सकेन्द्रण है। इन राज्यों के अलावा उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी सिक्ख जनसंख्या काफी बड़ी संख्या में है। जहां तक बौद्ध और जैन धर्म का संबंध है तो महाराष्ट्र में दोनों धर्मों की सबसे अधिक जनसंख्या

रहती है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त बौद्धों के पारम्परिक ठिकाने केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख, धर्मशाला (मेक्लोडगंज) और हिमाचल प्रदेश के निकट के जिलों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अतिरिक्त जैन धर्म के लोगों की बड़ी आबादी राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है।

पाठगत प्रश्न 22.4

1. भारत में कौन-से भाग में अधिकांश पारसी रहते हैं?
2. भारत के कौन-से राज्यों में इसाई रहते हैं?
3. भारत में मुस्लिम जनसंख्या के अधिक सकेन्द्रण वाले किसी एक राज्य का नाम लिखिए।
4. भारत के कौन-से राज्य में अधिकांश बौद्ध रहते हैं?

22.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संरचना और वितरण

भारत का संविधान कई जातियों और जनजातीय समूहों को मान्यता देता है। इन जातियों और जनजातीय को क्रमशः अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। वे भारत की जनसंख्या के प्रमुख अंग हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 16 प्रतिशत और 8.2 है। उनका वितरण पूरे देश में बहुत असमान है।

(क) अनुसूचित जातियां

संख्या की दृष्टि से उनका सबसे अधिक सकेन्द्रण उत्तर प्रदेश में है जिसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं। मिजोरम में अनुसूचित जाति की जनंसख्या नाममात्र है। नागालैंड और केन्द्रशासित क्षेत्र लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनसंख्या न के बराबर है। कुल जनसंख्या के भाग के रूप में इनकी जनसंख्या पंजाब में काफी अधिक है जहां वे कुल जनसंख्या का 28.85 प्रतिशत है। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में (24.7 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल में 23.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के लोग अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर, थोड़ी से भूमि पर कृषि करने वाले और छोटे उत्पादक अथवा कारीगर होते हैं। कृषि गतिविधियों के साथ जुड़ाव होने के कारण इनकी मुख्य आबादी जलोढ़ और तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसी कारण इनका प्रमुख संकेन्द्रण पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में पाया जाता है। दूसरी ओर मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत की जनजातीय पट्टी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत ही कम होती है। जिला स्तर के प्रतिरूप का विश्लेषण करने से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों (जोन) की पहचान होती है।

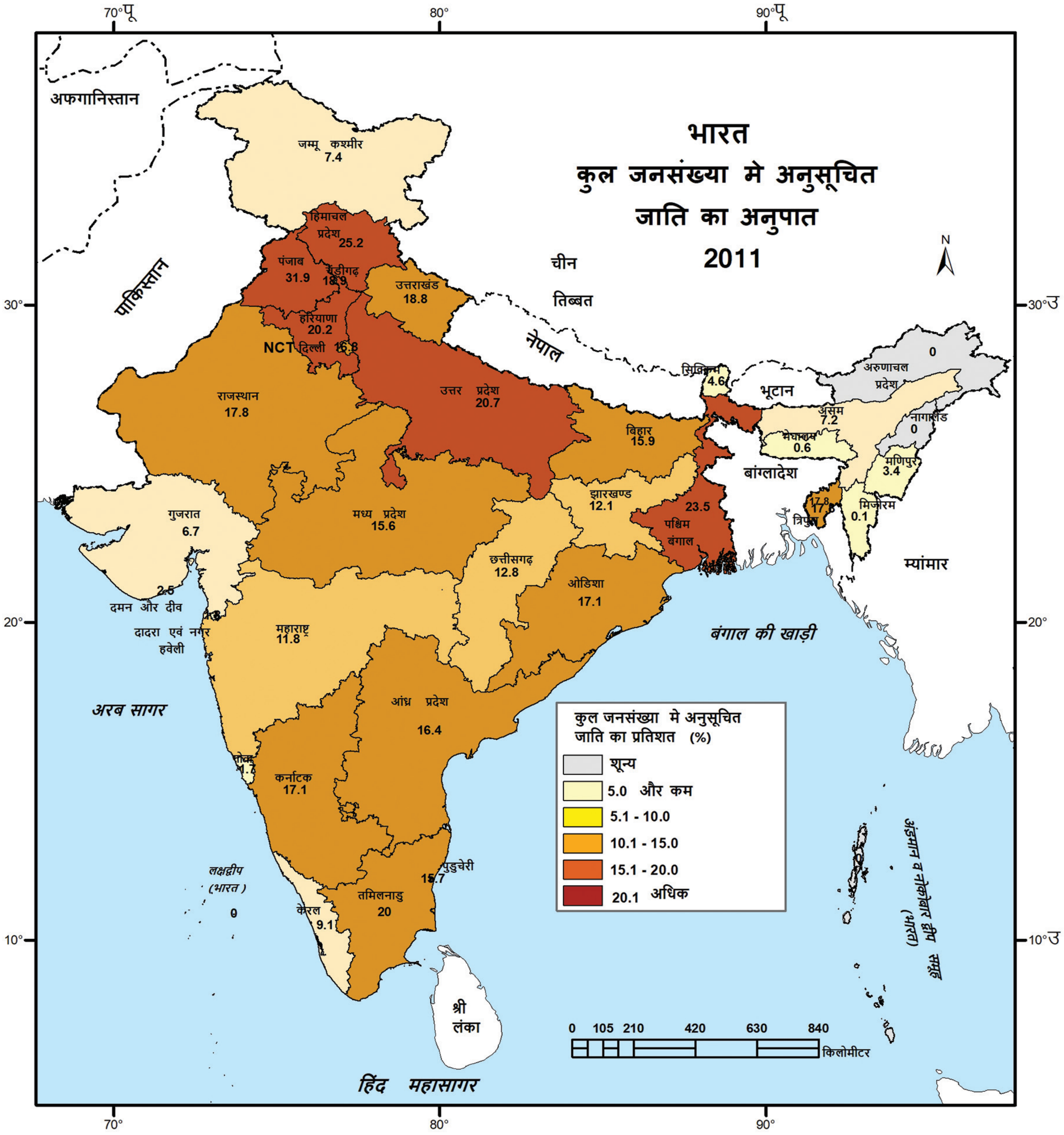

चित्र 22.4 भारत अनुसूचित जाति की जनसंख्या

1. **अधिक संकेन्द्रण वाले क्षेत्रः** अनुसूचित जातियों के अधिक संकेन्द्रण वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उनके नाम हैं गंगा मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इन दोनों मैदानों में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी की आपूर्ति और अनेक प्रकार की फसलों की खेती के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। इन अवसरों से सघन कृषि में सहायता मिलती है जो बड़ी जनसंख्या का सहारा बनती है।

2. **मध्यम संकेन्द्रण के क्षेत्रः** अनुसूचित जातियां उच्च संकेन्द्रण के साथ वाले जिलों में मध्यम रूप से संकेन्द्रित है, जिस पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

3. **कम संकेन्द्रण वाले क्षेत्र:** अनुसूचित जातियों का कम संकेन्द्रण मध्य विंध्याचल, छोटा नागपुर क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय भागों में पाया जाता है।

(ख) अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनेक अलग लक्षण और विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य लोगों से अलग करती हैं। प्राय: वे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में अकेले रहते हैं और बहुत प्राचीन धार्मिक विश्वासों को मानते हैं। इनमें से अधिकांश समूह निरक्षर हैं और उनकी अपनी भाषा की कोई लिपि नहीं है। उनमें से अधिकांश अलौकिक शक्तियों और अलौकिक प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। अनुसूचित जनजातियों का पूरे देश में वितरण एक समान नहीं है।

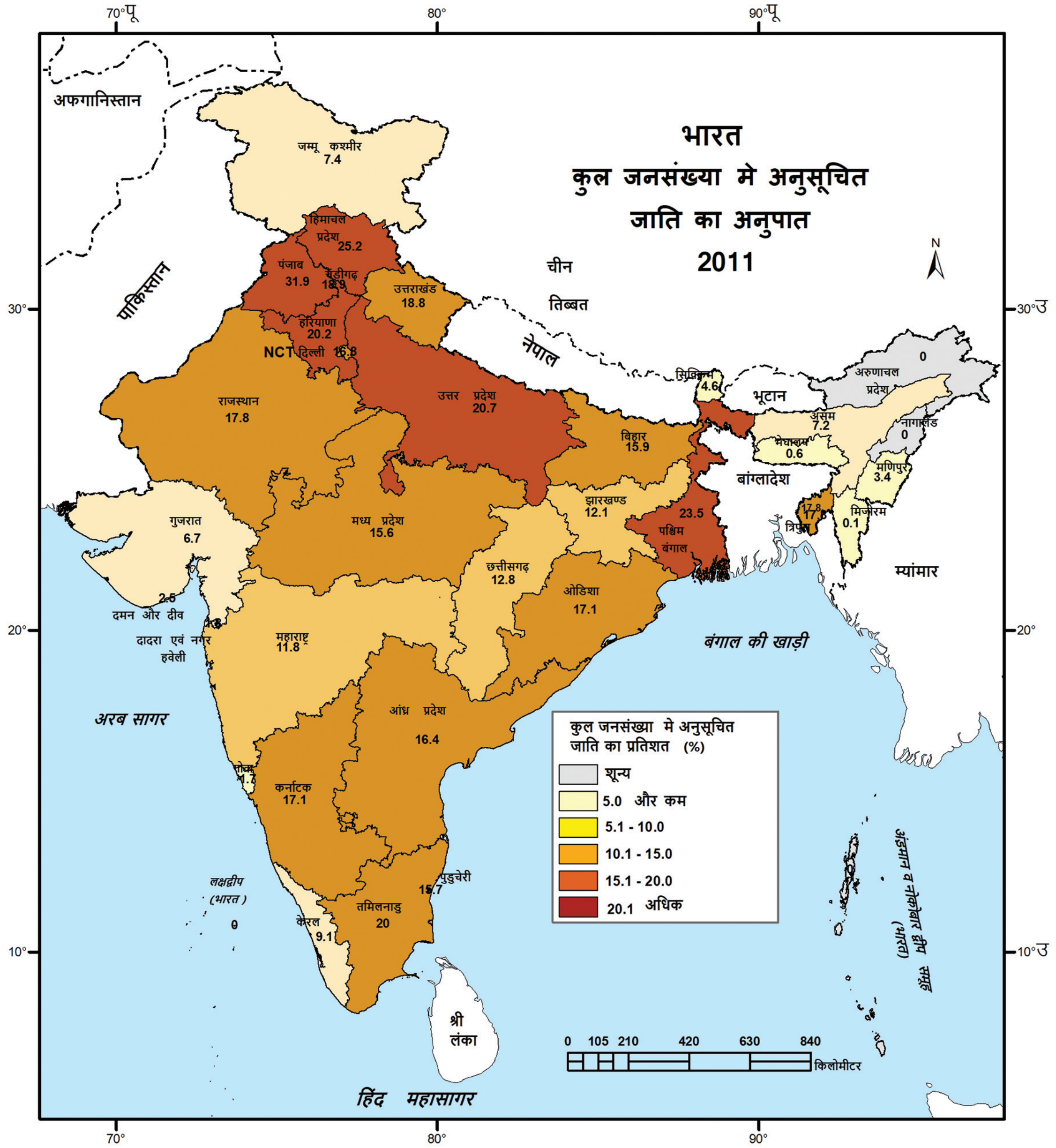

चित्र 22.5 भारत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

टिप्पणी

ऐसे तीन मुख्य क्षेत्र हैं जहां इस जनसंख्या के अधिकांश लोग रहते हैं-

1. मध्य भारतीय पट्टी, जिसमें राजस्थान के भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिनमें असम के पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

3. दक्षिण क्षेत्र जिनमें तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।

उपरोक्त चर्चा और उपरोक्त मानचित्र से स्पष्ट है कि भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण कुछ विशिष्ट भागों में ही है। मानचित्र के गहन अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकांश जनजातीय लोग जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों तथा कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्र प्राकृतिक कठिनाइयों से भरे होते हैं जैसे ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र, जलवायु की कठिनाइयां तथा इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास बहुत ही कम होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास नहीं हुआ है और वहां यातायात और संचार के साधनों का भी कम विकास हुआ है जिसके कारण वहां पर विकास कम हो पाता है। कभी-कभी यह सोचा जाता है कि जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विकास कम होने का कारण जनजातीय लोग ही हैं। यद्यपि यह सत्य नहीं है। वहां विकास कम होने का कारण इन क्षेत्रों में कठिन और असहनीय परिस्थितियों के फलस्वरूप केवल जनजातीय लोग ही वहां रहते हैं। वस्तुत: जनजातीय लोग मूल रूप से इन कठिन पर्यावरणीय स्थितियों में अपनी मर्जी से नहीं रहते। अपितु वे आधुनिक सभ्यता के विस्तार के कारण इन क्षेत्रों में धकेल दिए गए हैं। बार-बार के आक्रमणकर्ताओं और प्रवासियों के दबाव के कारण यहां पहले से बसे लोग शक्तिशाली आक्रमणकर्ताओं के साथ नहीं लड़ सके और विवश होकर उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ा।

22.7 साक्षरता

साक्षरता को प्राय: किसी व्यक्ति की लिखने, पढ़ने और समझने के साथ-साथ साधारण गणनाएं करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस उदारवादी परिभाषा के बावजूद भारत में साक्षरता अधिक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। इस प्रतिशत में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं। साक्षरता दर देश के एक भाग से दूसरे भाग तक बहुत बदल जाती है। एक तरफ केरल राज्य है जहां साक्षरता दर 94 प्रतिशत तक ऊंची है और दूसरी तरफ बिहार है जहां पर केवल 61.8 प्रतिशत है। केन्द्रशासित क्षेत्रों में लक्षद्वीप समूह की साक्षरता पर 91.85 प्रतिशत ऊंची है और दादर और नगर हवेली में यह दर 76.24 प्रतिशत के स्तर न्यूनतम दर है।

साक्षरता दर पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग है। भारत में पुरुष साक्षरता की औसत दर 82. 14 प्रतिशत है जो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत से अधिक है। केरल में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर क्रमश: 96.11 प्रतिशत और 92.07 प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है

टिप्पणी

जबकि बिहार में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर क्रमशः 71.20 प्रतिशत और 51.50 प्रतिशत है जो हमारे भारत की दृष्टि से न्यूनतम है। यद्यपि भारत में साक्षरता दर मध्यम है परंतु यह प्रतिवर्ष धीमे-धीमे बढ़ रही है। 1911 में यह 6 प्रतिशत से भी कम थी जो बढ़कर 1951 में लगभग 16. 7 प्रतिशत तक पहुंच सकी। इस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि 1951 के बाद हुई। 1961 में साक्षरता दर 24 प्रतिशत थी जो 2011 तक बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई। इस बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना यह रही कि स्त्रियों की साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिली।

1911 में स्त्रियों में केवल 1.1 ही साक्षर थीं परंतु 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गई। बहुत हद तक यह सरकार की नीतियों का परिणाम है जिसने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की सुविधा के विस्तार ने देश में साक्षरता दर को बढ़ाने में विशेषतः महिलाओं में, बहुत सहायता प्रदान की।

यद्यपि प्रत्येक जनगणना में साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन साक्षरों की निरपेक्ष संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। पहली बार 2001 की जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में गैर-साक्षरों की संख्या में कमी आई। यद्यपि उनकी संख्या अभी भी बहुत अधिक है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि।

पाठगत प्रश्न 22.5

1. नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

   a) भारत में जनजातीय जनसंख्या के अधिक संकेन्द्रण का एक क्षेत्र.................... है। (पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड)

   b) अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग........................ में रहता है। (उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब)

   c) भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर.................. थी। (65.38, 74.04, 68.01 प्रतिशत)

2. भारत सरकार द्वारा साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अपनाए गए किन्हीं दो कार्यक्रमों के नाम लिखिए।

   (i) .... (ii) ....

3. कौन-से राज्य में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर अधिकतम है?

आपने क्या सीखा

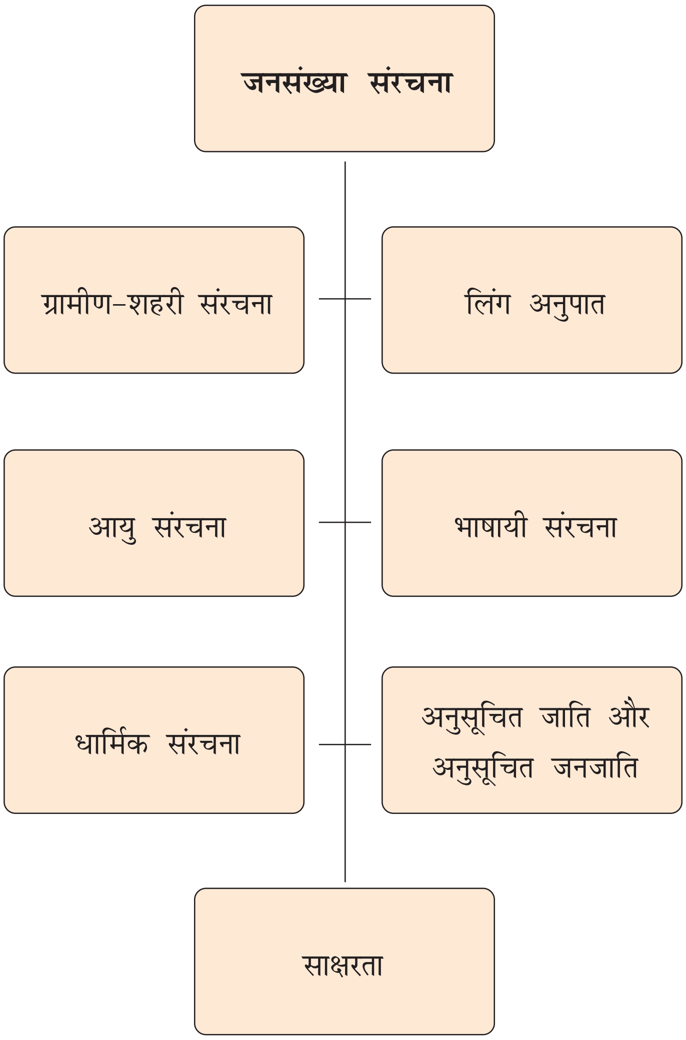

पाठांत प्रश्न

1. भारतीय जनसंख्या के निम्नलिखित लक्षणों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए-

   a) आयु संरचना

   b) शहरी ग्रामीण शोध

   c) लिंग अनुपात

2. भारत में साक्षरता का विवरण दीजिए।

3. लिंग अनुपात में कमी आने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? संक्षेप में चर्चा कीजिए।

4. भारत में जनजातीय जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए।

5. भारत की अधिकांश भाषाएं किस मुख्य भाषायी परिवार से सम्बन्ध रखती हैं? भारत में विभिन्न भाषायी परिवारों के वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

22.1

a) कम

b) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक

c) बढ़

d) 53

22.2

a) केरल

b) हरियाणा

c) 943

d) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात है।

22.3

a) संथाली

b) आर्यन

c) मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र

22.4

1. मुम्बई में एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र
2. तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य
3. उत्तर प्रदेश
4. महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश

22.5

1. a) झारखण्ड

   b) पंजाब

   c) 74.04
2. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि
3. केरल